

वित्त मंत्रालय
की
निर्गम परिणाम अनुवीक्षण रूपरेखा
(केन्द्रीय क्षेत्र एवं केंद्र प्रयोजित ₹500 करोड़ से कम लागत वाली योजना हेतु)

**OUTPUT OUTCOME MONITORING
FRAMEWORK**

(For Central Sector and Centrally Sponsored Schemes costing less than ₹500 crore)

**OF
MINISTRY OF FINANCE
2026-2027**

विषय सूची

क्रमांक संख्या	विभाग	पृष्ठ संख्या
1.	मांग संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग	1-2
i.	व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) योजना	1
ii.	भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) (सीएस)	2
2.	मांग संख्या 32 - वित्तीय सेवाएं विभाग	3-5
i.	अटल पेंशन योजना- प्रोत्साहन राशि, प्रचार अभियान	3
ii.	इंडो-स्विस सहयोग के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	4
iii.	कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी) और प्रचार संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना	5
3.	मांग संख्या 33 - लोक उद्यम विभाग	6
i.	सीपीएसईज़ से संबंधित सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान, विकास, परामर्श एवं पुनर्विन्यास।	6

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

1. व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) योजना

वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2026-27				परिणाम 2026-27			
	आउटपुट	क्र.सं.	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	क्र.सं.	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
100.01	व्यवहार्यता अंतराल निधियन के तहत पीपीपी के माध्यम से वित्तीय/ वाणिज्यिक अवसंरचना व्यवहार्यता में सुधार करना	1.1.	वित्तीय वर्ष के दौरान उन परियोजनाओं की संख्या जिन्हें सैद्धांतिक/ अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया	7	सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना में निजी क्षेत्र भागीदारी में सुधार	2.1.	अवसंरचना में कुल निजी निवेश प्रतिबद्धता (रुपये करोड़ में)	1449.70 करोड़
		1.2.	वित्तीय वर्ष के दौरान वीजीएफ योजना के तहत संवितरित निधियों की कुल राशि	100.00 करोड़				

2. भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2026-27						
2.5	पीपीपी मोड में, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की तैयारी के लिए तकनीकी सहायता	1.1. वित्तीय वर्ष के दौरान आईआईपीडीएफ के तहत सहायता प्राप्त नई परियोजनाओं की संख्या	15	अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित की गई।	1.1. वित्तीय वर्ष के दौरान उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें बोलियां आमंत्रित की गई।	12
		1.2. वित्तीय वर्ष के दौरान उन अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनमें संव्यवहार सलाहकार की नियुक्ति की गई है।	12			
		1.3. वित्तीय वर्ष के दौरान उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है।	10			
		1.4. वित्तीय वर्ष के दौरान उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है।	8			
		1.5. वित्तीय वर्ष के दौरान उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें डीपीआर/ बोली दस्तावेज तैयार किए गए हैं।	6			
		1.6. वित्तीय वर्ष के दौरान आईआईपीडीएफ के तहत संवितरित कुल धन राशि (करोड़ रुपये में)	2.5			

वित्तीय सेवाएं विभाग

ओओएमएफ 2026-27

योजना का नाम: 1) अटल पेंशन योजना- क. प्रोत्साहन, ख. प्रचार अभियान [2235.60.102.05.02.31, 2235.60.102.05.01.31]

वित्तीय परिव्यय (प्रस्तावित) (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27														
	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27												
340.75	अटल पेंशन (एपीवाई) सेवा प्रदाताओं (एसपी) को प्रोत्साहन राशि	एपीवाई सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन के लिए स्वीकृत राशि	प्रत्येक तिमाही में उपयोग की जाने वाली राशि (रुपये करोड़ में) <table border="1"> <tr> <td>तिमाही</td> <td>तिमाही</td> <td>तिमाही</td> <td>तिमाही</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	तिमाही	तिमाही	तिमाही	तिमाही	1	2	3	4					नामांकन और सततता में वृद्धि करता है	नामांकित अभिदाताओं की संख्या बनाए रखे गए अभिदाताओं की संख्या	बैंकों और डाक विभाग को नामांकन लक्ष्य दिए गए
तिमाही	तिमाही	तिमाही	तिमाही															
1	2	3	4															
5.00	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत प्रचार अभियान	प्रचार अभियानों के लिए स्वीकृत राशि	प्रत्येक तिमाही में उपयोग की जाने वाली राशि (रुपये करोड़ में) <table border="1"> <tr> <td>तिमाही</td> <td>तिमाही</td> <td>तिमाही</td> <td>तिमाही</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	तिमाही	तिमाही	तिमाही	तिमाही	1	2	3	4					बेहतर जागरूकता से अभिदाताओं को अधिक कवरेज और वृद्धावस्था सुरक्षा मिलेगी	नामांकित ग्राहकों की संख्या बनाए रखे गए ग्राहकों की संख्या	बैंकों और डाक विभाग को नामांकन लक्ष्य दिए गए
तिमाही	तिमाही	तिमाही	तिमाही															
1	2	3	4															

^ नामांकित ग्राहकों की संख्या के संबंध में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए परिणाम संकेतकों के लक्ष्यों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही तक सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा, तिमाही आधार पर अन्य लक्ष्यों को वितरित करना व्यवहार्य नहीं है चूंकि पीएफआरडीए द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के कार्य निष्पादन के आधार पर बैंकों और डाक विभागों को समग्र आधार पर वार्षिक लक्ष्य सौंपे जा रहे हैं।

योजना का नाम: 2) भारत-स्विस सहयोग के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान [2416.00.101.05.03.31]

वित्तीय परिव्यय (प्रस्तावित) (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
0.81	ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त	नाबार्ड को दावे के रूप में जारी की गई राशि	0.81	परिसंपत्ति निर्माण और पूंजी निर्माण के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना	इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र ऋण के विरुद्ध स्विस विकास निगम को भारत सरकार से देय पुनर्भुगतान/प्रतिबद्धताओं को शामिल करने के लिए एक विशेष निधि से नाबार्ड को पुनर्वित्त राशि जारी करना (करोड़ रुपये में)	0.81

* भारत-स्विस सहयोग के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान एक योजना नहीं है, यह एक करार है, इसलिए तिमाही आधार पर लक्ष्यों को वितरित करना व्यवहार्य नहीं है।

योजना का नाम : 3) कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (व्यक्ति-से-व्यापारी) [3465.01.187.01.02.31]

वित्तीय परिव्यय (प्रस्तावित) (करोड़ रुपए में)	परिव्यय 2026-27				परिणाम 2026-27		
	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27		आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,000	डिजिटल भुगतान की बढ़ती पैठ	यूपीआई स्वीकृति बुनियादी ढांचे में वृद्धि	10%		भीम-यूपीआई लेनदेन में वृद्धि	भीम-यूपीआई लेनदेन की संख्या में प्रतिशत वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2025-26 से वृद्धि %)	25%
		भीम-यूपीआई के माध्यम से (करोड़ में) व्यापारी डिजिटल भुगतान लेनदेन की संख्या (पी2एम)	18,187 करोड़				
			मात्रा (करोड़ में)	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4
				4,051	4,343	4,759	5,034

1. इसे संशोधित प्रोत्साहन योजना के नाम के अनुरूप करने के लिए मापदंडों को संशोधित किया गया है।
2. भीम-यूपीआई (पी2एम) और संवितरण के लिए तिमाही लक्ष्य पिछले साल के तिमाही कार्यनिष्पादन के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, तिमाही आधार पर अन्य लक्ष्यों को संवितरित करना संभव नहीं है, क्योंकि वे सक्षमता और ऑनबोर्डिंग डेटा पर भरोसा करते हैं।

वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

1. अनुसंधान, विकास, परामर्श एवं पुनर्विन्यास (आरडीसीआर) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
6.75	1. सीपीएसई और एसएलपीई ^[1] से संबंधित सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करना।	1.1 सीपीएसई/एसएलपीई के बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या जिसमें सीपीएसई के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली पर प्रशिक्षण शामिल है।	10	1. सीपीएसई और एसएलपीई के लिए व्यापक मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का उपयोग।	1.1 विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल किए गए सीपीएसई/एसएलपीई की संख्या।	25
		1.2 किए जाने वाले अनुसंधान/विषयगत अध्ययनों की संख्या।	1		1.2 विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल किए गए सीपीएसई/एसएलपीई की संख्या।	25
		1.3 सीपीएसई के कार्यपालकों/निदेशकों के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं की संख्या।	5		1.3 विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत भाग लेने वाले/प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या।	150
		1.4 सीपीएसई के निदेशक मंडल के लिए आयोजित होने वाले अभिविन्यास कार्यक्रमों की संख्या।	3		1.4 विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत भाग लेने वाले/प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या।	50
		1.5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ किए गए सहयोगों की संख्या।	1		1.5 विभिन्न कार्यकलापों के तहत शामिल किए गए सीपीएसई (महारत्न और नवरत्न) की संख्या	19

[1] सीपीएसई - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम; एसएलपीई - राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम।

INDEX

Sl. No.	Departments	Page no.
1.	Demand No. 30- Department of Economics Affairs	9-10
i.	Viability Gap Funding (VGF) Scheme	9
ii.	India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) (CS)	10
2.	Demand No. 32-Department of Financials Services	11-13
i.	Atal Pension Yojana-Incentive, Promotional Campaign, Gap Fund	11
ii.	Grants to NABARD to settle claims under Indo-Swiss Cooperation	12
iii.	Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (person-to-merchant) and Promotional Activities	13
3.	Demand No.33 – Department of Public Enterprises	14
i.	Research Development, Consultancy & Reorientation (RDCR) on Generic issue related to CPSEs.	14

Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

1. Viability Gap Funding (VGF) Scheme

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2026-27				1. OUTCOMES 2026-27			
	2026-27	Output	S.No.	Indicators	Targets 2026-27	Outcome	S.No.	Indicator
100.01	Improve financial/commercial viability of infrastructure projects through PPP under Viability Gap Funding	1.1.	No. of projects granted In-Principle/Final Approval during the FY	7	Improved Private Sector participation in Social and Economic Infrastructure	2.1.	Total private investment committed in infrastructure (in Rs. Crores)	1449.70
		1.2.	Total amount of funds disbursed under the VGF Scheme during the FY	100.00 Cr.				

2. India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2026-27			OUTCOMES 2026-27		
	2026-27	Output	Indicators	Targets 2026-27	Outcome	Indicators
2.5	Technical Support for preparing quality infrastructure projects, in PPP mode	1.1. No. of new projects supported under IIPDF during the FY	15	Inviting Private Sector participation in infrastructure	1.1. No. of projects in which bids are floated during the FY	12
		1.2 No of approved projects in which TA is appointed during the FY	12			
		1.3 No of projects in which Inception Report is prepared during the FY	10			
		1.4 No of projects in which Feasibility Report is prepared during the FY	8			
		1.5 No of projects in which DPR/ bid documents are prepared during the FY	6			
		1.6 Total amount of funds disbursed under IIPDF (Rs in Cr) during the FY	2.5			

Ministry of Finance
Department of Financial Services

OOMF 2026-27

Name of Scheme: 1) Atal Pension Yojana- a. Incentive, b. Promotional Campaign [2235.60.102.05.02.31, 2235.60.102.05.01.31]

Financial Outlay (proposed) (Rs.in Cr)	Output 2026-27			Outcome 2026-27										
	Output	Indicators	Targets 2026-27	Outcome	Indicators	Target 2026-27								
340.75	Incentive to Atal Pension (APY) Service Providers (SPs)	Amount Sanctioned for Incentive to APY SPs	Amount to be utilised in each quarter (in Rs. crore) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Qtr 1</td> <td>Qtr 2</td> <td>Qtr 3</td> <td>Qtr 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4					Increases enrolments and persistency	Number of subscribers enrolled Number of subscribers retained	^Enrolment targets given to Banks and Department of Post
Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4											
5.00	Promotional Campaign under Atal Pension Yojana (APY)	Amount sanctioned for Promotional campaigns	Amount to be utilised in each quarter (in Rs. crore) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Qtr 1</td> <td>Qtr 2</td> <td>Qtr 3</td> <td>Qtr 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4					Better awareness leading to more coverage and old age security to the subscribers	Number of subscribers enrolled Number of subscribers retained	^Enrolment targets given to Banks and Department of Post
Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4											

^Targets for outcome indicators for FY 2026-27 in respect of number of subscribers enrolled would be finalized with the approval of the competent authority by the 1st Quarter of FY 2026-27. Further, it is not feasible to distribute other targets on quarterly basis, as annual targets are being assigned by PFRDA to Banks and D/o Post on aggregate basis, based on the performance of previous FY.

Name of Scheme: 2) Grants to NABARD to settle claims under Indo-Swiss Cooperation [2416.00.101.05.03.31]

Financial Outlay (proposed) (Rs.in Cr)	Output 2026-27			Outcome 2026-27		
	Output	Indicators	Targets 2026-27	Outcome	Indicators	Target 2026-27
0.81	Refinance by NABARD for non-farm sector to increase the flow of credit by banks for non-farm activities in rural areas	Amount released as claims to NABARD	0.81	Promotion of non-farm sector, through asset creation and capital formation	Release of refinance amount to NABARD from a Special Fund to cover repayments/ commitments due from Gol to the Swiss Development Corporation against the Rural Non-Farm Sector credit under the project (in Rs. Cr)	0.81

**Grants to NABARD to settle claims under Indo-Swiss Cooperation is not a Scheme, it is an agreement, therefore, it is not feasible to distribute targets on quarterly basis.*

Name of Scheme: 3) Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (person-to-merchant) [3465.01.187.01.02.31]

Financial Outlay (proposed) (Rs.in Cr)	Output 2026-27				Outcome 2026-27				
	2026-27	Output	Indicators	Targets 2026-27	Outcome	Indicators	Target 2026-27		
2,000	Increased penetration of Digital Payments	Increase in UPI acceptance infrastructure	10%				Growth of BHIM-UPI transactions	Percentage increase in the number of BHIM-UPI Transactions (% increase from FY 2025-26)	25%
		Number of merchant Digital Payment transactions (P2M) via BHIM-UPI (in crore)	18,187 crore						
			Volume (in Crore)	Q1	Q2	Q3	Q4		
				4,051	4,343	4,759	5,034		

- Parameters are modified to align it with the revised incentive scheme name.
- The quarterly targets for BHIM-UPI (P2M) and distribution have been set based on last year's quarterly performance. However, it is not feasible to distribute other targets on a quarterly basis, as they rely on enablement and onboarding data.

Ministry of Finance
Department of Public Enterprises

1. Research, Development, Consultancy and Reorientation (RDCR) (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2026-27				OUTCOMES 2026-27			
	2026-27	Output	Indicators	Targets 2026-27	Outcome	Indicators	Target 2026-27	
6.75	1. To undertake research studies, training, seminars, workshops on generic issues related to CPSEs and SLPEs ^[1]	1.1	No. of Training Programs for Below-Board Level Executives of CPSEs / SLPEs conducted including training on performance appraisal system for CPSEs.	10	1. Utilization of Research Studies, Training and Workshops on Generic issues to CPSEs and SLPEs	1.1	No. of CPSEs/ SLPEs covered under various activities	25
		1.2	No. of Research/Thematic Studies to be undertaken	1		1.2	No. of CPSEs/ SLPEs covered under various activities	25
		1.3	No. of Workshops for Executives/ Directors of CPSEs to be held	5		1.3	No. of persons participated/trained under various activities	150
		1.4	No. of orientation programs for Board-of Directors of CPSEs to be held	3		1.4	No. of persons participated/trained under various activities	50
		1.5	No. of collaborations with national & international organizations.	1		1.5	No. of CPSEs (Maharatna & Navratna) covered under various activities	19

^[1] CPSE- Central Public Sector Enterprise; SLPE- State Level Public Enterprise

